SHRI JESUDASU SEELAM: There is an error. It is stated: "The proposed amendments in the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2006 broadly fall under the following categories, namely, inclusion of new castes based on social, educational and economic backwardness." Sir, in respect of Scheduled Castes, this term 'economic backwardness' has not been there in the Constitution. It is, I think, strictly put in to create so much unrest. I request that that should not form part of the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN:. That should be taken note of.

SHRI JESUDASU SEELAM: That should be deleted, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

"That the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2006 be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRIMATI MEIRA KUMAR: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned for half-an-hour.

The House then adjourned at thirty-three minutes past three of the clock.

The House reassembled at seven minutes past four of the clock, MR DEPUTY CHAIRMAN in the Chiar.

SHORT DURATION DISCUSSION

Heavey floods in various parts of the country and the relief measures undertaken by the Government

श्री कलराज मिश्र (**उत्तर प्रदेश**) **:** माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रो में आए हुए संकट के बारे में बोलने का अवसर प्रदान किया हैं, इसके लिए अत्याधिक धन्यवाद । मान्यवर, इस सत्र में प्रति वर्ष बाढ़ पर चर्चा होती हैं और इतना ही नहीं, कुछ प्राकृतिक आपदाएं ऐसी हैं जो हमेशा आती हैं –बाढ़, सूखा, भूकंप, पर्वतीय क्षेत्रो में भूस्खलन, हिमरखलन, ये ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो आम आदमी के जीवन को त्रस्त करती हैं, इनसे हजारों-करोड़ों रुपयों की क्षति होती हैं, सैकड़ो-हज़ारों जानें जाती हैं, पशुओं की क्षति होती हैं, फसलों की क्षति होती है और लोग इनसे जूझते हैं । इस वर्ष भी भारत के कई हिस्सों में भयंकर बाढ़ का प्रकोप दिखाई

पड़ा । बाढ़ की विभीषिका ऐसी रही कि चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आंध्र हो, चाहे उत्तर भारत में बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे जम्मू-कश्मीर हो –इन इलाको में कोई हिमखंड से पीड़ित हैं, तो कोई बाढ़ से पीढ़ित है और इस समय जिस प्रकार के हालात उत्पन्न हुए हैं, इनके बारे में अतंर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी लोगों ने चिंताएं जाहिर करनी शुरू की हैं । और दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत जिन देशों में इस प्राकृतिक आपदा से क्षति हुई हैं, जीवन की हानि हुई हैं, उसमें विशेष रूप से भारत, नेपाल बंग्लादेश और श्रीलंका हैं । इन चारों देशों में मिलाकर 3 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति प्रभावित हुए हैं, 2 करोड़ से ज्यादा बेघर भी हुए हैं, 3 हजार से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई हैं । क्षति अत्याधिक हुई हैं । भारत में जिस तरीके की स्थिति निर्माण हुई हैं और जिन प्रदेशों में बाढ़ से क्षति हुई है, वे प्रदेश अगर हम देखें तो आंध्र में 9.19 लाख लोग प्रभावित हुए, 51 की मृत्यु हुई, 12 जिले प्रभावित हुए, 1329.97 लाख रुपए की क्षति हुई । आसम और पूर्वोत्तर भारत में 69.48 लाख आबादी प्रभावित हुई, 35 की मृत्यु हुई, 26 जिले इसमें ज्यादा प्रभावित हुए । बिहार में लगभग डेढ़ करोड़ की आबादी प्रभावित हुई, 171 की मृत्यु हुई, 19 जिले प्रभावित हुए और 30452.22 लाख रुपय की क्षति हुई । गुजरात में 7.9 लाख लोग प्रभावित हुए, 281 की मृत्यु हुई, 22 जिले अत्यधिक प्रभावित हुए और 4630.32 लाख रुपए की क्षति हुई ? केरल में भी, मान्यवर इसी प्रकार का हुआ । 17.09 लाख लोग प्रभावित हुए, 221 लोगों की मृत्यु हुई, 7 जिले प्रभावित हुए और 65186.17 लाख रुपए की क्षति हुई । उत्तर प्रदेश में 18.70 लाख आबादी प्रभावित हुई, 167 की मृत्यु हुई, 22 जिले इसमें ज्यादा प्रभावित हुए । पश्चिम बंगाल में लगभग 68.46 लाख लोग प्रभावित हुए, 167 की मृत्यु हुई, 3 जिले प्रमुख रूप से प्रभावित हुए और 15684.13 लाख रुपए की क्षति हुई ।

इसके अलावा अन्य प्रांत भी विशेष रूप से उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश जम्मू-कश्मीर इसमें जिस तरीके से यमुनोत्री ग्लेश्यिर फटा हैं और यमुनोत्री ग्लेश्यिर फटने के कारण ऊपर रहने वाले लोग पानी से प्रभावित हुए, यानि ऊपर बाढ़ आ गई और ऐसी हालात पैदा हो गई हैं कि लोग वहां से कैसे निकलें, यह समस्या खड़ी हो गई हैं । हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू-कश्मीर भी इससे सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं । हमने क्षति का जो आकलन किया हैं, जो एक सर्वेक्षण आया था, उसके आधार पर किया हैं । यह क्षति शायद बहुत कम हैं । देखने में, इससे कहीं ज्यादा क्षति हुई हैं । यह प्रकोप, यह आपदा जिस तरीके से आया हैं, जिसे प्रकार का निर्माण हुआ हैं, वहां जाकर क्षति की स्थिति का अंदाजा तो लगाया नहीं जा सकता हैं । आपदा के अंतर्गत सभी लोगों के सामूहिक सहयोग की अपेक्षा रही हैं । केवल सत्ता पक्ष इसके लिए काम करे या बाकी के लोगों को, राजनीतिक लोग इसमें काम करे, यही अपेक्षा नहीं रहती हैं । जब इस प्रकार की आपदा आती हैं तो चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे सामाजिक संस्थाएं हो, वाहे अन्य लोग हो, सब लोग सामूहिक रूप से मिलकर लोगों को सहयोग देने के लिए आगे बढ़ते हैं तो समाज में एक-दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ता हैं । और आगे आने की स्थिति का निर्माण होता हैं । इन्हीं सारी स्थितियों को देखकर, विशेषकर मुझे तो लगा, मैंने देखाकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी संयुक्त राष्ट्र बालकोष, UNICEF जिसको कहते हैं, और विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिन्होंने विशेष रूप से इधर की तरफ ध्यान दिया और उनको लगा कि जैसी हालत निर्माण हुई हैं, ऐसी स्थिति में आगे चलकर भयंकर महामारी आएगी और इन देशों में, जिनका मैंने उल्लेख किया –भारत, श्रीलंका, बंगलादेश और नेपाल – ये इससे सर्वाधिक प्रभावित होंगे और भारत तो सर्वाधिक करनी चाहिए । उनकी तरफ से और इन देशो में, जिनका मैंने उल्लेख किया – भारत, श्रीलंका, बंगलादेश और नेपाल – ये इससे सर्वाधि प्रभावित होंगे और भारत तो सर्वाधिक प्रभावित होगा । इसके गांवो के अंदर महामारी निर्माण हो जाएगी और उसके लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए । उनकी तरफ से भी इस प्रकार का चिंतन करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और चिंतन करने के क्रम में एक धम्रार्थ संस्था OXFAM हैं इन्होंने भारत के अंदर बीस लाख डॉलर जुटाने की

लोगों से अपील की हैं । कनाडा के अंदर भी इन्होंने दस लाख अमेरिकी डॉलर देने का मन बनाया हैं । उधर के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ऐसी प्राकृतिक आपदा के समय सहयोगात्मक मानसिकता से प्रेरित होकर जो काम करते हैं, उनकी तरफ से इस प्रकार की चीज़ आई हैं । इसलिए मान्यवर, यह जो स्वरूप दिखाई पड़ा हैं, यह बड़ा भयंकर दिखाई पड़ा हैं । इधर उत्तर भारत के अंदर बाढ़ की विभीषिका निर्माण हुई । उत्तर भारत के अंदर दिखाई पड़ा हैं । इधर उत्तर भारत के अंदर बाढ़ की विभीषिका निर्माण हुई । उत्तर भारत के अंदर, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, इसका सर्वाधिक शिकार हुआ हैं, विशेषकर उत्तर बिहार । उत्तर बिहार में तो नेपाल से निकलने वाली नदियां सर्वाधिक प्रभावित करती है । वे नदियां हैं – कोसी, जो बड़ी नदी हैं, बागमती, गंड़क, बूढ़ी गंडक- ये नदियां इतना प्रभावित करती हैं कि उधर आम लोग हमेशा त्रस्त होते हैं । पूर्वी उत्तर प्रदेश में राप्ती, रोहिया, गंडक छोटी गंडक, इन नदियां के कारण तबाही का स्वरूप निर्माण होता हैं । चाहे बस्ती हो, चाहे सिद्धार्थनगर हो चाहे संते कबीर नगर हो, चाहे गोरखपुर हो, महाराजगंज हो, देवरिया हो, कुशीनगर हो, ये सारे ज़िले बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं । इसी ढंग से उत्तर बिहार के अंदर इन नदियों के प्रकोप के कारण पूरे उत्तर बिहार में 19 ज़िले सर्वाधिक प्रभावित हुए । मान्यवर हुए । मान्यवर, मैं मुजफ्फरपुर गया था । वहां मैंने देखा, लगता था कि बड़े भयंकर समुद्र का निर्माण हुआ हो । एक अजीब प्रकार की स्थिति का निर्माण हुआ । लोग कैसे रहते हैं, कैसे अपनी आजीविका चलाते हैं, यह देखकर बड़ा आश्चर्य लगता हैं और ऐसे में लोगों की व्यवस्था बड़ी अपेक्षित रहती हैं । लोग अनुभव करते हैं कि कोई आकर हमारी समुचित तौर पर देखभाल करे, हमारी चिंता करे, हमें बचाए, इस प्रकार की लोग कोशिश भी करते हैं और मान्यवर, मैं इतना कह सकता हूं कि इस प्राकृतिक आपदा के अतंर्गत आलोचना, प्रत्यालोचना का कोई स्थान नहीं होना चाहिए । जिसको जहां से हो सके, वहां से मदद करने के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए, चाहे शासकीय स्तर पर हो, चाहे सामाजिक और अन्य स्तर पर हो । स्वेच्छया आगे बढ़कर काम करने की दृष्टि से जाना चाहिए ।

महोदय, मैं बिहार में संबंध में इतना जरूर कहूंगा कि बिहार के मुख्य मंत्री उस समय मॉरीशस में थे । कुछ लोगों ने आलोचनाएं की, मैं समझता हूं कि वह आलोचना उचित नहीं थी, करना भी नहीं चाहिए । इस समय तो अगर कहीं कमी दिखी हैं, तो कमी को दूर करने के लिए साथ में मिलकर, सामूहिक रूप से कैसे लोगों को व्यवस्थित करने की दिशा में प्रयत्न किया जाए, यह कोशिश करनी चाहिए लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि बिहार में सारी चीजों से निपटने के लिए बिहार सरकार ने जो काम किया, निश्चित रूप से, मैं यह तो नहीं कहुंगा कि उन सारे कामों से सब लोग संतुष्ट हो गए होंगे या सबकी अपेक्षा पूरी हो गई होगी । ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन काफी मात्रा में उन्होंने करने की कोशिश की । मान्यवर, जैसा मैंने पहले ही बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं । बिहार में 19 जिलें हैं । उन उन्नीस जिलों में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चम्पारन, पश्चिमी चम्पारन, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौढ, मधेपुरा, खगरिया, बेगूससय अररिया, कटिहार, गोपालगंज, भागलपुर, पटना और नालंदा हैं । ये 19 जिले सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं । इसमें प्रखंडों की संख्या के भी हमारे पास आंकड़े आए हैं कि कुल 185 प्रखंड प्रभावित हुए हैं । इसी प्रकार 1290 पंचायतें प्रभावित हुई हैं, 6,602 गांव प्रभावित हुए हैं । इसी प्रकार जनसंख्या का मैंने बताया कि डेढ़ करोड़ के आस-पास लोग प्रभावित हुए हैं । फसल की क्षति 11.8 लाख हेक्टेयर हुई हैं, क्षतिग्रस्त फसलों का अनुमानित मूल्य 9,609.61 लाख रुपए हैं । सार्वजनिक सम्पत्ति की क्षति भी हुई हैं । उसकी निश्चित संख्या नहीं आ पायी हैं, वे 102 के लगभग हैं । इसमें जो कार्य किए गए हैं, मैं उनका उल्लेख जरूर करना चाहूंगा । चलाई गयी नावों की संख्या 4,239 हैं । जो लोगों को बाहर ले जाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश की गयी, उनमें लगभग 1 लाख लोग हैं । सहायता कैम्पों की जो व्यवस्था की गयी, वे 846 हैं । इसी प्रकार

233 चिकित्सा कैम्प हैं और 243 पशु कैम्प है । इसके अतिरिक्त 62,544.25 क्विंटल गेहूं दिया गया, 18.199.70 क्विंटल चावल दिया गया, 5.592 क्विंटन चिवड़ा दिया गया, 849.45 क्विंटन गुड दिया गया । इसके अलावा वितरित नकद अनुदान 1,17.618 रुपए हैं । 7,388 मोमबत्तियों का वितरण किया गया । इसके अलावा दियासिलाई का भी वितरण किया गया, जिसकी संख्या 35,923 हैं । ये चीज़े हेलीकॉप्टर से जगह-जगह गिरायी गयी । मान्यवर, आलोचनाएं होती थी कि कुछ नहीं किया गया हैं – ऐसा नही हैं । मान्यवर, भरसक करने की कोशिश की गयी ताकि जो लोग परेशान हैं, प्रभावित हैं, उनको सर्वाधिक मात्रा में मदद पहुंचाकर आश का संचार किया जाए । सब लोग एकजुट होकर इसमें लगे हुए हैं और सरकार भी इसके लिए सदा जागृत हैं और उसके अनुरूप काम करने का प्रयत्न कर रही हैं ।

महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में जो बाढ़ के भयंकर प्रकोप का निर्माण होता हैं, उसका एक कारण यह भी है कि नेपाल से बड़ी तेली से प्रवाहित होकर नदियां चलती हैं और उसको रोकने के लिए-चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या बिहार की सरकार हो-जो बांध बनाए हैं, उन बांधो से अस्थायी रोक तो होती हैं लेकिन जब तेज प्रवाह से आने वाले पानी से वे बांध टूट जाते हैं तो पूरा इलाका ध्वस्त हो जाता हैं और एक ऐसी स्थिति का निर्माण हो जाता हैं कि जबर्दस्त बरसात होने के बाद भी जैसा स्वरूप दिखायी नहीं पड़ता हैं, वही बांध के टूट जाने के बाद पूरी की पूरी जमीन और आबादी को वह अपने में समेट लेता हैं । सारा का सारा जलमग्न हो जाता हैं । यही स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार में निर्मित हुई हैं । बांध बुरी तरह से टूटे और बांध के टूटने के कारण इस स्थिति का निर्माण हुआ हैं । और इसलिए हर बार बाढ़ के बारे में चर्चा होने के बाद बार-बार यह बात आती हैं कि नेपाल गवर्नमेंट और भार सरकार दोनों को मिलकर इसके लिए कोई न कोई स्थाई समाधान निकालना चाहिए । लेकिन वह समाधान नहीं निकल पा रहा हैं । दोनों सरकारों को शामिल रूप में बैठ करके जो विचार करने की स्थिति निर्माण होनी चाहिए वह निर्माण नहीं हो पा नही है और इसलिए एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई हैं । यह बात सही हैं कि पहले जब बाढ़ आती थी तो बाढ़ आने के समय भी वहां जो धान पैदान होता था, और धान की जो फसल होती थी तो बाढ़ के अंदर भी लोग नाव से चलकर उसको काट लेते थे । उस तरह का बीज था, फसल थी यह हमारे भंडारी जी वगैरह सब लोग जानते होंगे । लेकिन अब वह भी नही हैं । अब फसल तो नष्ट हो ही जाती हैं, जीवन की हानि होती ही हैं । इतना सब होने के बावजूद समाधान नहीं निकल पा रहा हैं । पशुओं का हालत व पशुओं की क्षति तो इतनी भयंकर हो रही हैं कि पशु चारे के बगैर मर रहे हैं, उनको चारा नहीं मिल रहा हैं । चारा कहां से दिया जाए, आदगी को तो अन्न मिल जाता हैं लेकिन पशुओं को चारा नहीं मिलता हैं । पशु तो बुरी तरह से बह जाता हैं और भूखे मर जाता हैं । यह एक विचित्र स्थिति निर्माण हुई हैं, इसका स्थाई समाधान चाहिए । लेकिन स्थाई समाधान नहीं निकल पा रहा हैं । स्थाई स्माधान निकलने के क्रम में जरूर विचार करना चाहिए, चाहे छोटे बांध हो या बड़े बांध हों, चाहे और भी कोई विकल्प हों, उनके बारे में विचार करना चाहिए । अभी तक के जो विकल्प हैं, इन विकल्पों की तुलना के आधार पर अध्ययन करना चाहिए । एक विकल्प तो यह हैं कि सीधे-सीधे बांध खड़ा कर दिया जाए और उसके आधार पर पानी के प्रवाह को रोका जाए । यह खर्चे वाला हैं और इसमें पैसा भी ज्यादा लगता हैं । लेकिन यह उस प्रवाह को बर्दास्त नहीं कर पाता हैं और टूट जाता हैं तो बड़ा नुकसान होता हैं । दूसरा, गतिशील बांध बनाने के बारे में है । इससे रोका तो जा सकता हैं लेकिन बनाना ज्यादा कठिन हैं । इसलिए अनेक प्रकार की तकनीकी गड़ड़ियां पेदा हो सकती हैं । तीसरा जो विकल्प हैं, जब 2001-2002 में जो बजट आया था उस समय की सरकार के द्वारा जल संसाधन कं बजट के अंतर्गत यह बात कही गई थी कि बाढ़ की विभिषिका को रोकने के लिए विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर ऊंचा स्थान बनाया जाए । उसके लिए बजट भी आबंटित करने की कोशिश की गई थी और कहा गया था कि लोगों को रहने के लिए ऊंचे स्थान पर रखा जाए बाढ़ में जीने की एक ऐसी

मानसिकता बनाई जाए, यानी जिससे उनको क्षति भी न हो, संचार की भी व्यवस्था हो सके और लोग ऊंचे स्थानों पर रह सकें। जो नदियों का सिल्ट हैं, उससे रहने का स्थान ऊंचा बनाते हुए बिना बांध के उस पानी के प्रवाह को रोकने का प्रयत्न करना और बाढ़ के अंतर्गत भी कम्युनिकेशन की सुविधा देना और बाकी अन्य चीजों के बारे में भी विचार किया जा सकता हैं। एक व्यवस्था या यह विकल्प यह भी प्रस्तुत किया गया था और उसके लिए पैसे का आवंटन भी किया गया था, लेकिन वह चल नहीं पाया। तो ये तीन विकल्प हो सकते हैं जिनके बारे में विचार करना चाहिए। नदियों को जोड़ने का भी एक विकल्प हैं, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के अन्तर्गत नदियों को जोड़ने-रिवर्स कनेक्टिविटी की बात की गई थी। नदियों को जोड़ने के माध्यम से दोनों चीजें सम्भावित है। यदि बाढ़ की विभिषिका बहुत अधिक बढ़ जाए तो उससे बाढ़ को रोक भी सकते हैं। अगर चारों तरफ जबर्दस्त बरसात हो रही हैं तो शायद रिवर्स कनेक्टिविटी से परेशानी भी पैदा हो जाए। अगर एक तरफ बरसात हुई हैं तो रिवर कनेक्टिविटी से लाभ भी हो सकता हैं। तो यह भी एक विकल्प हो सकता हैं। लेकिन इसके समाधान के लिए प्रभावी विकल्प की आवश्यकता हैं, प्रभावी योजना बनाने की जरूरत हैं, तभी हम बाढ़ के प्रकोप से अपने को रोक सकते हैं और जो प्रति वर्ष इस प्रकार की चर्चा का अवसर प्राप्त होता हैं शायद उस चर्चा का अवसर न प्राप्त हो। लेकिन स्थाई समाधान निकालने की आवश्यकता हैं। इस चर्चा के माध्यम से मैं ये सब चीजें आपके बीच में रखना चाहता हूं। मान्यवर, इन सारी बातों को रखते हुए मैं इतनी अपेक्षा जरूर करता हूं कि इस बात को हम विशेष रूप से इस ढंग से लेकर के चलें कि सबका दायित्व हैं…. हम केन्द्र सरकार की आलोचना कर दें और किसी स्टेट गवर्नमेंट की आलोचना कर दें और कोई किसी के बारे में कुछ आरोप लगा दे, इससे काम चलने वाला नहीं हैं। सामूहिक रूप से, मिल-बैठकर इस समस्या का समाधान हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसके लिए अच्छे-अच्छे तकनीकी के जानकार लोगों को बुलाकर समुचित व्यवस्था कर सकते हैं। अगर इस प्रकार की चीजें हम कर सकें, तो मैं समझता हूं कि एक अच्छी स्थिति का निर्माण होगा और स्वस्थ सोचने की परम्परा होगी और इसी आधार पर, मैं सोचता हूं कि इसी दिशा में सोचकर जो प्रभावित लोग हैं, उनको अधिकाधिक सहयोग प्रदान करने के लिए हमारी बिहार की सरकार ने एक परिपत्र दिया था, एक मेमोरेंडम केन्द्र सरकार को दिया था। उन्होंने अपेक्षा की थी कि जितनी क्षति हुई हैं, जो भी चीज़ मांगी जा रही हैं, उसको सरकार जरूरर दे। आश्वासन तो केन्द्र सरकार ने जरूर दिया हैं, कब मिलता है पता हैं, इन-पुट सब्सिडी फार एग्रीकल्चर के लिए 100 करोड़ रुपये की मांग की हैं, वाटर रिसोर्स सैक्टर के लिए 79.29 करोड़ रुपये की मांग की हैं, हाउस डेमेज के लिए 18.44 करोड़ रुपये की मांग की हैं कम्युनिकेशन के लिए 332.86 करोड़ रुपये की मांग की है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए 63.44 करोड़ रुपये की मांग की हैं, अदर सैक्टर के लिए 400.51 करोड़ की मांग की हैं और सब मिलाकर 3220.102 करोड़ की मांग की हैं। मैं इस सदन के माध्यम से अपेक्षा करूंगा कि सरकार इनकी उपयुक्त मांग के बारे में विचार करते हुए प्रभावितों की मदद करें, ताकि बिहार के जो आम लोग प्रभावित हुए हैं, उनको ठीक तरह से लाभान्वित किया जा सके। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के बारे में भी गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो लोग सर्वाधिक प्रधावित हुए हैं, वे लाभान्वित किया जा सके। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के बारे में भी गंभीरपूर्वक विचार करते हुए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो लोग सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं, वे लाभान्वित हो सके, उनकी चिंता करें। मैं इतनी बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI DWIJENDRA NATH SHARMAH (Assam): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak. Sir, flood in the country this year has affected many States. Previously we have been observing that flood was almost an annual feature particularly in the State of Assam. But this year it has been observed that Assam, Bihar, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Orissa, Gujarat, Kerala, almost all

the States have been affected by floods, maybe, some for a short period and some for a long period. 1 would like to speak on certain points with which my State is concerned, particularly the flood which has affected my State this year. Sir, the flood in Assam is a perennial problem. After the 1950 earthquake the riverbeds of Brahmaputra and other tributaries have come up and because of that since 1950 Assam is facing every year very devastating flood and by which lakhs of people have to lose their houses and the economy collapses. At the same, it becomes very difficult to make the economy grow in the State of Assam. This year, Sir, you will be surprised that out of 27 districts, 26 districts have been affected. Sir, 5962 villages, and 66.17 lakh people have been affected in the last flood. We have lost 27 human lives in this flood and the total area affected this year is 8.66 lakh hectares. The crop area, which has been affected, is 3.54 lakh hectares and 9291 houses have been damaged this year in the recent flood. Breaches to embankments were 69. Number of PWD roads damaged were 773. Number of temporary wooden bridges damaged were 66, number of bridge approaches damaged were 461. RCC bridge approaches damaged were 25. Number of breaches on PWD roads were 54. Total length of PWD road breaches were 1256 metres. These are the effects of recent floods this year. Sir, we have been this mentioning for a long time and several times in this House also I spoke on floods. In the last Session also, 1 spoke on floods of how my State was suffering because of this devastating flood. Now, the problem is, we have to see how we can control this devastating flood, this dangerous situation which our people face from time to time. One thing is, we have been observing, that embankments have been constructed in different rivers but that has not given result and there is breach of embankments every year. Lot of money has been spent after independence for controlling floods but people are not getting any result and it is increasing day by day. The most affected people are the village people, particularly, the farmers, the cultivators who lost all their standing crops, houses etc. at such a time. Now, we have to see how we can control this situation, how we can come to a permanent solution of this problem, how we can control floods in our State. The only thing is, some experts say that dredging of rivers, deepening of rivers is most important at this stage because silting of rivers have created such floods. All the rivers, embankments and the riverbanks have become equal. It has come to such a stage that when there is rainfall, water immediately crosses the embankments and the whole area is flooded. This year also we have seen rainfall in Assam. It was 835 mm during June and July. In Arunachal Pradesh it was 921 mm during June and July. We are very much nearer to Arunanchal Pradesh. The rain which comes to Arunachal Pradesh immediately comes to the valley of Assam and it creates flood. Another cause of flood is deforestation in the hilly areas and deforestation in different parts of the hilly states. Since deforestation has created floods in Lakhimpur. and other districts, they feel that power projects have sensed the ecology in that area because of huge construction of power projects.. Our people think it may not be correct but there is an apprehension that those projects have also created floods this year in Lakhimpur districts and Dhemaji districts of Assam. Now, Sir, we think that a permanent solution for this problem is necessary for the State of Assam and a solution which can help us should be considered by the Government so that our people are saved from this annual dangerous situation which happens in Assam every year. Now, Sir, dredging of Brahmaputra river and tributaries is very essential at this point and, I hope, the Government will take up such programmes so that dredging can be taken up and silts can be removed from the rivers and one permanent fund is necessary. Since it is happening every year one permanent fund is necessary for, Assam by which immediate action can be taken so that people who are affected by flood every year can

be given relief immediately. Though there is an annual relief system, though there is a Central Government Fund but there are certain essential, certain emergency measures are necessary for which a special fund is necessary for Assam so that at that point of time our people can get relief and shelter when they are suffering because of floods. Our Home Minister and the UPA Chairman, Smt. Sonia Gandhi had already visited Assam. They had assured that all possible steps would be taken for relief and rehabilitation of the flood-affected people. Sir, 1 don't want to take much time, but 1 would request the Government to go for a permanent solution for controlling the river Brahamaputra and its tributaries so that we can save our people, we can save our cultivators, we can save our farmers from the devastating effects of floods. With these words, I conclude, Sir.

श्री बृजभूषण तिवारी (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, अभी बाढ़ की चर्चा करते हुए माननीय सदस्यों ने इसकी गंभीरता और इसके गंभीर दुष्परिणामों की तरफ सदन का ध्यान खींचा हैं। यह सही हैं कि बाढ़ पर हर साल चर्चा की रस्म अदागयी होती हैं, परंतु अभी तक बाढ़ की रोकथाम के लिए कोई मुकम्मत तरीका अख्तियार नहीं किया गया हैं। चर्चा हैं कि आपदा राहत का क्या मतलब होता हैं। आपदा राहत का मतलब होता हैं जो नुकसान हो गया, अगले वर्ष उतना ज्यादा नुकसान न होने पाए। परंतु जो दृष्टि और नजरिया हमारी सरकार और प्रशासन का हैं, वह केवल एडहोकिज्म, वक्ती तौर पर हैं। हमारे यहां पर सरकार तब जागती हैं, जब बाढ़ चौखट पर आ जाती हैं। इसलिए मान्यवर, आज केवल इस पर ही चर्चा होनी हैं कि बाढ़ से कितना नुकसान हुआ हैं, बल्कि इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि आखिर इस नुकसान का जिम्मेदार कौन हैं। अगर इसके लिए सरकार या उसके प्रशान के अधिकारी जिम्मेदारी हैं तो उनकी जवाबदेही क्या हैं। यह सही हैं कि हमारा एशिया पेसिफिक क्षेत्र हैं, वह ऐसा है कि जितनी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उसका साठ प्रतिशत यह भोगताहैं। इसका कारण इसकी भौगोलिक स्थिति हैं, यहां के मौसम का उतार-चढ़ाव हैं, यहां का भूगर्भ या ज्योलाजिकल फैक्टर हैं। परन्तु इस समय देश में बाढ़ से जो सबसे ज्यादा प्रभावित बाइस सूबे हैं, अभी प्रधानमंत्री जी ने अपने बयान में स्वीकार किया कि इन बाइस या बीस सूबों में करीब पंद्रह सौ लोगों की मौत हो गई। माननीय कलराज जी ने अभी काफी तफसील से अन्य प्रदेशों के नुकसान के बारे में, क्षति के बारे में आंकड़े पेश किए। मैं उन आंकड़ों को दोहरा कर सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता, परंतु इस बार की बाढ़ का सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में और बिहार के उत्तरी क्षेत्र में हैं। अभी गृह मंत्रालय की ओर से हम लोगों को एक प्रस्तिका मिली हैं। इसमें स्वयं स्वीकार किया गया हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में करीब 2,540 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से 2,540 गांवो में 1,091 से ज्यादा गांव ऐसे हैं, जो जलमग्न हैं, चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं, जहां पर आने-जाने का कोई रास्ता नहीं हैं। मान्यवर, यह मामला केवल एक दिन, दो दिन, चार दिन या एक हफ्ते का नहीं हैं। यह सही हैं कि नदियों का जलस्तर गिर रहा हैं, परन्तु जिन इलाकों में पानी फैल गया हैं, वहां पानी के रिसने का, पानी के निकास का जो क्रम हैं, वह इतना हैं कि आज भी बहुत से गांव चारों तरफ पानी से डूबे हुए हैं। अब आप कल्पना करिए कि हवाई सफर से या हेलिकॉस्टर से उनके व्यक्ति चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हैं, उसके सामने कई विकट समस्याएं हैं, समस्या हैं, जो दैनिक क्रिया हैं, उसके निपटान की और उसमें भी जो सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात हैं, वह यह हैं कि उन गांवों की जो महिलाएं हैं, आप उनकी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं और अगर आप इंसार हैं, तो आप सिहर जाएंगे। उसके बाद जो पानी जन्य रोग हैं, वह भी भयकर। वह इतना प्रदूशित जल हैं, उसकी जो बदबू हैं, उसकी जो सड़न हैं और उससे जो नाना प्रकार के रोग फैल रहे हैं, उसके सम्बन्ध में सरकार और प्रशासन मैं तो यह कहूंगा कि अग्रेजी में callous है और हिन्दी में उसको निष्ठुर कहा जाता

हैं । मैं अभी सिद्धार्थनगर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में घूम रहा था । मुझे वहां के गांव वालों ने बताया कि 15 दिन हो गए थे, सारा इलाका पानी मे डूबा हुआ, मगर न तो कोई मुख्लाय मुश्किल से 8 किलामीटर और जिला मुख्यालय मुश्किल से 25 किलोमीटर की दूरी पर हैं । कोई भी हाल लेने नहीं गया । जो मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं या नेता हैं, उन्होंने हवाई सफर कर दिए और बड़ी-बड़ी घोषणाऐं कर दीं और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने तो कमाल ही कर दिया । यह हवाई दौरा करके गई और उन्होंने एक स्वर में कह दिया कि बाढ़ की सारी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और इसके लिए नेपाल और केन्द्र की सरकार, ये दोनों ही जिम्मेदार हैं । उनका अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं हैं । उनके पास उनका कलक्टर हैं, उनका तहसीलदार हैं उनका डिप्टी हैं, उनके इंजीनियर्स हैं और यह रूल्स में हुआ हैं कि बाढ़ के पहले जिला स्तर पर जिले-जिले में सब लोगों की एक मीटिंग होती हैं । उसमें जनप्रतिनिधि भी आमंत्रित किए जाते हैं और बाढ़ के सिलसिले में क्या तैयारी हैं, क्या इंतजाम करने हैं, कैसे बाढ़ से निबटना हैं, उसके बारे में विशद चर्चा होती हैं और एक कार्य योजना तैयार होती हैं । मान्यवर, मैंने जानकारी की ओर मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अधिकांश, दो-तिहाई से ज्यादा जिले ऐसे हैं, जहां पर बाढ़ के पहले इस प्रकार की कोई मीटिंग या इस प्रकार की कोई बैठक नहीं हुई । उत्तर प्रदेश की सरकार बड़ी चुस्त और दुरुस्त मालूम देती हैं, देती हैं, उनको तो केवल लोगों की जांच और केवल हरकाने के अलावा और कोई काम नहीं हैं,फर्जी मुकदमा दायर करने के अलावा कोई काम नहीं हैं । क्या यह उनकी जवाबदेही नहीं हैं कि वह अपने अधिकारियों के मार्फत पता करें कि किन-किन जिलों में इस प्रकार की मीटिंग हुई और अगर यह मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया और उसका कहां तक पालन किया गया ? मैं यह जानना चाहता हूं ।

इसी के साथ ही साथ, बाढ़ में जो राहत बॉटी जा रही हैं, 20 किलों चावल, कहीं 20 रुपए, कहीं 50 रुपए, कहीं 10 रुपए, वह भी पूरी तरह से नहीं दिया गया । अब अगर आपको तजुर्बा हो, अनुभुव हो, तो अक्सर होता यह हैं कि केवल एक ही बार बटता है उसके बाद फिर कोई उस गांव में झोकने नहीं आता । वह एक बार बंट गया सो बंअ गया । अब आपने पूरी बाढ़ के दौरान अगर पांच आदमियों के परिवार को 20 किलों चावल दे दिए, तो वह क्या खाएगा ? वह भूख से मरेगा या नहीं मरेगा ?

मान्यवर, यह बाढ़ की मार भी बड़ी विचित्र हैं । इसकी चपेट में कौन आता हैं ? इसकी चपेट में गरीब आदमी आता हैं, खेतिहर मज़दूर आता हैं या किसान आता हैं । हां इस बार यह अवश्य हुआ हैं कि बाढ़ का रूप और आकार बदला हैं । अब यह बाढ़ मुम्बई में भी आने लगी हैं, दिल्ली को भी सताने लगी हैं, महानगरों के लोगों को भी उसकी पीड़ा सहनी पड़ रही हैं, और वहां भी हाहाकार मचने लगा हैं । अभी तक तो सिर्फ गांव वाले ही उससे तबाह होते थे । मुझे याद हैं कि एक बार संसद में यहां पर इस विषय पर चर्चा हो रही थी, बात-बात में तत्कालीन प्रधान मंत्री आदरणीय श्री जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा कि बाढ़ से बहुत फायदे हैं । उस समय लोहिया जी भी सदन में मौजूद थे, उन्होंने तपाक से कहा कि अच्छा होता कि यह बाढ़ दिल्ली में भी आती या उस संसद मे भी आ जाती तो उन्हें भी यह फायदा मिल जाता । आज यही हो रहा हैं । दिल्ली मुम्बई और अन्य महानगरों मे भी यह बाढ़ रही हैं । आज बाढ़ का आकार बढ़ता जा रहा हैं, उसके दुष्परिणाम और भी अधिक खतरनाक होते जा रहे हैं, इसलिए इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए ।

मान्यवर, दूसरी बात यह हैं, जैसा कि अभी श्री कलराज जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार की जितनी भी नदियां हैं, ये नेपाल से आती हैं । एक महाकाली योजना थी, जिस पर भार और नेपाल का समझौता हुआ था, परन्तु यह जो केन्द्र की सरकार हैं, यह इतनी उदासीन रही कि उस पर जो पहल करनी चाहिए थी, उस पहल नहीं की गई । अगर पहले की गई ।